

अन्याय के बंदी: कैसे इज़राइल की हिरासत प्रणाली और हमास की बंधक रणनीति पीड़ा का एक चक्र बनाए रखती है

इज़राइलियों और फ़िलिस्तीनियों के बीच चल रहा संघर्ष दुखद रूप से बंदियों के चक्र में प्रतिबिंबित होता है: इज़राइल की मनमानी हिरासत, यातना, और फ़िलिस्तीनियों के अमानवीकरण की प्रणाली, और इसके जवाब में हमास द्वारा बंधक बनाना। दोनों प्रथाएँ असीम पीड़ा पहुंचाती हैं। फ़िलिस्तीनी निरंतर इस खतरे में जीते हैं कि वे बिना उचित प्रक्रिया के एक प्रणाली में गायब हो जाएंगे, जबकि इज़राइली अपने प्रियजनों के लिए शोक मनाते हैं जो सशस्त्र समूहों द्वारा बंदी बनाए गए हैं। परिणामस्वरूप, आधात, क्रोध, और कटूरपंथ का एक निरंतर चक्र चलता रहता है।

इस चक्र को तोड़ा जा सकता था—हाल ही में अक्टूबर 2023 में बातचीत के ज़रिए हुए समझौतों के माध्यम से, जो दोनों पक्षों के बंदियों को मुक्त कर सकते थे। लेकिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में इज़राइल की सरकार ने, चरमपंथी तत्वों के दबाव में, कूटनीति के बजाय तनाव बढ़ाने का रास्ता चुना, प्रमुख वार्ताकारों को हाशिए पर डाल दिया और पीड़ा को लंबा खींच दिया। इज़राइल के गैरकानूनी हिरासत शासन को समाप्त करने से इनकार और कूटनीतिक चैनलों की अस्वीकृति ने दर्द के इस चक्र को और गहरा कर दिया।

इज़राइल का हिरासत शासन: संस्थागत अन्याय

1967 से, इज़राइल ने कब्जे वाले फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों में प्रशासकीय हिरासत और सैन्य अदालतों को नियंत्रण के साधन के रूप में उपयोग किया है। ये तंत्र पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय कानूनी मानदंडों के बाहर काम करते हैं। फ़िलिस्तीनियों को बिना किसी आरोप या मुकदमे के अनिश्चितकाल के लिए कैद किया जा सकता है, गुप्त साक्ष्यों के आधार पर, बिना किसी प्रभावी अपील के साधन के। सैन्य अदालतें, जिनका दोषसिद्धि दर लगभग 99.7% है, न्याय के बजाय दबाव के साधन के रूप में कार्य करती हैं। ये प्रथाएँ मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (अनुच्छेद 9 और 10), नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय संधि (अनुच्छेद 9 और 14), और चौथे जेनेवा कन्वेंशन (अनुच्छेद 64-66) का सीधे उल्लंघन करती हैं।

यातना और दुर्व्यवहार व्यवस्थित हैं। संयुक्त राष्ट्र निकायों और मानवाधिकार संगठनों की कई रिपोर्टों में मारपीट, तनावपूर्ण मुद्राओं, वॉटरबोर्डिंग, बिजली के झटके, यैन अपमान, और वस्तुओं के साथ बलात्कार के उपयोग को दर्ज किया गया है। 2015 की एक रिपोर्ट में 2005 और 2012 के बीच कम से कम 60 यैन यातना के मामलों को सूचीबद्ध किया गया। ये कृत्य यातना के खिलाफ कन्वेंशन (अनुच्छेद 1 और 16) और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय संधि के अनुच्छेद 7 का उल्लंघन करते हैं, जो किसी भी परिस्थिति में यातना को निषिद्ध करते हैं।

7 अक्टूबर, 2023 के बाद से, ये दुर्व्यवहार नाटकीय रूप से बढ़ गए हैं। अगस्त 2024 तक, कम से कम 53 फ़िलिस्तीनी बंदी हिरासत में मर चुके थे, जिनमें से कई पर यातना के निशान थे। 14 साल की उम्र के बच्चों को जबरन नग्नता और अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ा। वास्तव में, ऐसी परिस्थितियों में रखे गए फ़िलिस्तीनी न केवल अपनी स्वतंत्रता से वंचित हैं, बल्कि अपनी मानवता से भी। व्यवस्थित प्रकृति और नागरिक आबादी पर दबाव डालने के इरादे को देखते हुए, ये कृत्य संभवतः 1979 के बंधक लेने के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन के तहत बंधक लेने की परिभाषा को पूरा करते हैं, जिसमें व्यक्तियों को चोट या मृत्यु की धमकी के तहत हिरासत में रखना शामिल है ताकि किसी तीसरे पक्ष—इस मामले में, फ़िलिस्तीनी समाज—को कार्य करने के लिए मजबूर किया जाए।

फ़िलिस्तीनी समाज में मनोवैज्ञानिक तबाही

मनमानी हिरासत से होने वाला आघात जेल की दीवारों से कहीं आगे तक फैलता है। परिवार निरंतर इस डर में जीते हैं कि उनके प्रियजन—विशेष रूप से बच्चे—रात में ले जाए जाएंगे, बिना संपर्क के हिरासत में रखे जाएंगे और यातना दी जाएगी। कई फ़िलिस्तीनियों के लिए, “गिरफ्तारी” शब्द का मतलब उचित प्रक्रिया नहीं है—इसका मतलब है गायब होना, हिंसा, और संभवतः मृत्यु। 2024 तक, 9,500 से अधिक फ़िलिस्तीनी हिरासत में लिए गए थे, जो सामूहिक आतंक और शोक को बढ़ावा देता है।

यह व्यापक पीड़ा निष्क्रियता को जन्म नहीं देती, बल्कि प्रतिरोध को। जवाबों की तलाश में निराश परिवार और समुदाय अक्सर उन एकमात्र संगठनों की ओर मुड़ते हैं जो प्रभाव का वादा करते हैं—सशस्त्र समूह। यह हिंसा का औचित्य नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक वास्तविकता की स्वीकृति है: जब आपका बच्चा गैरकानूनी रूप से कैद है, यातना दी जा रही है, और इसकी बहुत अधिक संभावना है कि आप उसे फिर कभी जीवित नहीं देखेंगे, तो उसकी वापसी सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी करने की प्रवृत्ति गहराई से मानवीय है। यह मनोवैज्ञानिक अनिवार्यता, हालांकि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत कोई बचाव नहीं है, हमास की रणनीति को समझने की कुंजी है।

हमास की बंधक लेने की रणनीति: गैरकानूनी लेकिन समझ में आने वाली

7 अक्टूबर, 2023 को, हमास ने 251 इज़राइली बंधकों को पकड़ लिया, जिसने दुनिया को झकझोर दिया। यह कार्य **1979 के बंधक कन्वेंशन** के तहत गैरकानूनी और नैतिक रूप से असमर्थनीय था, जो सरकार से कार्यवाही के लिए नागरिकों को पकड़ने को स्पष्ट रूप से निषिद्ध करता है। फिर भी, हमास ने इस रणनीति को खाली जगह में नहीं बनाया—इसका ऐतिहासिक मिसाल और मनोवैज्ञानिक तर्क है।

2011 में गिलाद शालित कैदी विनिमय, जिसमें एक इज़राइली सैनिक के बदले 1,000 से अधिक फ़िलिस्तीनियों को रिहा किया गया, ने फ़िलिस्तीनियों के बीच यह धारणा मजबूत की कि केवल बंधक लेना ही परिणाम देता है। चूंकि इज़राइल की कानूनी प्रणाली हिरासत में लिए गए लोगों के लिए न्याय का कोई रास्ता नहीं देती, हमास बंधकों को सौदेबाजी के चिप्स के रूप में उपयोग करता है—एक नैतिक रूप से घृणित लेकिन राजनीतिक रूप से प्रभावी रणनीति। फिर से, उद्देश्य इस कार्य का बचाव करना नहीं है, बल्कि इसके मूल कारण का सामना करना है: एक समाज जो यह मानने के लिए कूरता से मजबूर किया गया है कि कूटनीति और कानूनीता का कोई मूल्य नहीं है।

नैतिक और कानूनी समानता इसलिए विधियों—बंधक लेने और हिरासत—में नहीं है, बल्कि उनकी अंतर्निहित गैरकानूनीता और अमानवीय प्रभाव में है। इज़राइल की मनमानी हिरासत और हमास की बंधक लेने की रणनीति दोनों ही अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करती हैं और दोनों नागरिकों को निशाना बनाती हैं। एक को राज्य द्वारा मंजूरी दी जाती है, यह नियमित है और कानूनी नौकरशाही में लिपटे हुए है; दूसरी शानदार और तात्कालिक है। लेकिन दोनों एक ही जबरदस्ती, आघात, और निराशा के चक्र का हिस्सा हैं।

साझा पीड़ा

इज़राइली पक्ष में दुख गहरा है। बंधकों के परिवार असहनीय अनिश्चितता को सहते हैं, यह जानने में असमर्थ कि उनके प्रियजन जीवित हैं या नहीं, और यह तो दूर की बात कि वे कब या कैसे लौटेंगे। उनकी पीड़ा उन फ़िलिस्तीनी परिवारों की पीड़ा को प्रतिबिंబित करती है जो एक अलग नाम के तहत वही अनुपस्थिति, भय और असहायता का अनुभव करते हैं: “प्रशासकीय हिरासत”।

इस समानांतर पीड़ा को सहानुभूति के लिए जगह बनानी चाहिए थी। इसके बजाय, इसे हथियार बनाया गया है। इज़राइल में युद्धविराम और बंधक समझौते की मांग करने वाले प्रदर्शनकारियों को नजरअंदाज किया गया या खारिज कर दिया गया। इज़राइली बंधकों के परिवार, जिनमें हाइम रुबिन्स्टीन जैसे लोग शामिल हैं, ने नेतन्याहू सरकार पर अपने प्रियजनों को राजनीतिक लाभ के लिए बलिदान करने का सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया है।

छूटी हुई संभावना और नीतिगत विफलता

इस रसातल से बाहर निकलने का एक रास्ता मौजूद था। अक्टूबर 2023 में, गेर्शोन बास्किन के नेतृत्व में पर्दे के पीछे की वार्ताएँ, जिनमें कठोर और हमास के संपर्कों की मध्यस्थता थी, ने पारस्परिक रिहाई के लिए एक व्यवहार्य ढांचा पेश किया। लेकिन नेतन्याहू की कट्टर सरकार, जिसमें इतामार बेन-गिर और बेज़ालेल स्मोत्रिच जैसे अल्ट्रानेशनलिस्टों का वर्चस्व था, ने इन प्रस्तावों को खारिज कर दिया। ओरेन सेटर, जो उस समय बंधक वार्ताओं में एक प्रमुख अधिकारी थे, ने छूटी हुई संभावना के विरोध में इस्तीफा दे दिया।

यह एक सामरिक गलती नहीं थी—यह एक नैतिक विफलता थी। मानवीय समाधान के बजाय सैन्य तनाव को प्राथमिकता देने से न तो इज़राइलियों और न ही फिलिस्तीनियों को मुक्ति मिली। इसने दर्द को गहरा किया, और अधिक कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया, और बंदियों के युद्ध के हाथियार के रूप में उपयोग को और मजबूत किया।

चक्र को तोड़ना

इस चक्र को समाप्त करना हवाई हमलों या बंधक बचाव के साथ शुरू नहीं होता, बल्कि उन संरचनाओं को ध्वस्त करने के साथ शुरू होता है जिन्होंने उन्हें आवश्यक बनाया। इज़राइल को अपनी मनमानी हिरासत प्रणाली और सैन्य अदालतों को समाप्त करना होगा—ऐसी प्रथाएँ जो कानून के शासन को नष्ट करती हैं और हिंसक प्रतिशोध को जन्म देती हैं। इस मूलभूत अन्याय को संबोधित किए बिना, कोई भी अस्थायी युद्धविराम या विनिमय केवल अगले अपहरण और रक्तपात के चक्र को विलंबित करेगा।

न्याय चयनात्मक नहीं हो सकता। वही सिद्धांत जो हमास की बंधक लेने की निंदा करते हैं, उन्हें इज़राइल द्वारा नागरिकों की अनिश्चितकालीन, गैर-न्यायिक कारावास को भी अस्वीकार करना होगा। जब तक दोनों प्रकार के बंदीकरण को समाप्त नहीं किया जाता, दोनों लोग एक ऐसे तंत्र के बंदी बने रहेंगे जो आपसी पीड़ा पर फलता-फूलता है।